सिद्ध किया है । मैसर्स पाइराइट्स, फास्फेट्स एंड केमिकल्स लि०, ने ब्रिटेन की एक फर्म, मैसर्स आर. टी. जैड को इन भंडारों की संभाव्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए नियुक्त किया है ।

(ख) और (ग) इस राज्य के राक-फास्फेट्स तथा पाइराइट्स भंडारों पर आधारित राजस्थान में एक उर्वरक संयंत्र स्थापित करने के बारे में राजस्थान सरकार के अनुरोध पर भारत सरकार ने राजस्थान में एक उर्वरक उद्योग समूह स्थापित करने की संभाव्यता का अध्ययन करने के लिए एक कार्यकारी दल नियुक्त किया था । कार्यकारी दल ने राजस्थान में इस प्रकार का उद्योग समूह स्थापित किए जाने की संभावना व्यक्त की है । इन भंडारों के व्यापारिक उद्योग के पश्चात् उद्योग समूह की स्थापना करने के लिए आगामी कार्यवाही किए जाने पर विचार किया जायेगा ।

*[THE MINISTER OF LAW AND JUSTICE AND PETROLEUM AND CHEMICALS (SHRl H. R. GOKHALE): (a) The Geological Survey of India have indicated a possible ore reserve of 115 million tonnes of various grades of pyrites in Blocks A, B, C & D in Saladipura. M/S Pyrites, Phosphates and Chemicals who are doing the Exploratory-cum-Mining work of these pyrites have so far proved 6 million tonnes of ore out of a total reserve of about 25 million tonnes pyriles of about 25% sulphar grade indicated in Block 'A'. M/S Pyrites, Phosphates and Chemicals Ltd. have engaged M/S R T Z Consultants Ltd., a U.K. firm, to prepare a feasibility report on these reserves.

(b) and (c) On a request from the Government of Rajasthan in regard to the setting up a fertilizer plant in Rajasthan based on the r«ck-phosphates and pyrites deposits in the State, a Working Group was set up by the Government of India to look into the feasibility of setting up of a fertilization complex in Rajasthan. Th» Working Group has indicated the possibility of establishing such a complex in Rajasthan. Further action towards the establishment of the complex will be considered after the commercial exploitation of these deposits is established.]

+f t Rrmtich trnnclntinn

J PRICE OF JUTE

339. SHRI SITARAM KESRI: Will the Minister of FOREIGN TRADE *he* pleased to state:

(a) whether the Agriculture Price Commission has recommended the fixation of a statutory minimum price for jute; and

(b) if so, the sters taken to implement the recommendations ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOREIGN TRADE (SHRI A. C. GEORGE): (a) and (b) The Report of the Agricultural Prices Commission on price policy for raw jute for the 1972-73 season has been received and is under consideration. Government's decisions in the matter are expected to be announced shortly.

—

CALLING ATTENTION TO AMATTER OF URGKNT PUBLICIMPORTANCE

REPORTED ACTIVITIES OF THE CIA IN BORDER DISTRICT OF BIKANER AND GANGANAGAR

श्री जगदीश प्रसाद माथुर (राजस्थान) : श्रीमन्, मैं राजस्थान विश्वविद्यालय में काम कर रहे कुछ विदेशी शोध छात्रों के माध्यम से जो संयुक्त राज्य अमरीका के स्टेट डिपार्टमेंट के पाकिस्तान सम्बन्धी अनुभाग और वहां के रक्षा मंत्रालय से संबंधित हैं, बीकानेर और संगानगर के सीमावर्ती जिलों में सी. आई. ए. की गतिविधियों के समाचार की ओर गृह मंत्री का ध्यान दिलाता हूं ।

*Transferred from the 12th May, 1972

[MR. DEPUTY CHAIRMAN in the Chair]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (WILL ALSO ASSIST THE PRIME MINISTER IN PARLIAMENTARY WORK RELATING TO DEPATMENTS OF ATOMIC ENERGY AND ELECTRONICS) (SHRI K. C. PANT): Sir, of the two indi-i viduals mentioned, Dr. Darel A. Frohrib a has not been granted any visa nor is there any information of his having visited the country. Mr. Richard Newton Blue was granted visa valid for 10 months'stay in India up to 20th July, 1972 for undertaking research on some aspects of agricultural administration, with special reference to Rajasthan. He was staying at Jaipur and is known to have visited Bikaner in November, 1971, for sight-seeing. There is no information of his having visited Ganganagar District. Nothing adverse has come to the notice of Government with regard to his activities.

12 NOON

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : उपसभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने संक्षिप्त वक्तव्य देकर के इस विषय की महत्ता को कम करने का प्रयास किया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि राजस्थान युनीवर्सिटी के प्रोफेसर इकबाल नरायण और कानपुर युनीवर्सिटी के मि० शर्मा, ये दोनों अमेरिका गये थे और अमेरिका में मि० ब्लू और मि० फ्रोरिब के साथ उन्होंने ज्वायन्ट स्टडी की दृष्टि से वहां पर एक प्रोजेक्ट तैयार किया था। आपने लोक सभा में बतलाया था कि वह प्रोजेक्ट सेंक्शन्ड नहीं था। यह बात मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि वह इसलिए सेंक्शंड नहीं है, लेकिन क्या यह बात सही है और मंत्री जी को यह मालूम होगा कि वे पाकिस्तानी डेस्क से सम्बन्धित थे और वे हिन्दुस्तान में आये जब कि उनको वीसा ग्रान्ट नहीं किया गया था। इन बातों की जानकारी प्राप्त होने के बाद भी हिन्दुस्तान की सरकार ने उसको वीसा ग्रान्ट नहीं किया, लेकिन उनके जो दूसरे साथी थी, ब्लू थे, वे हिन्दुस्तान में आ गये। हिन्दुतान में उनके साथ काम करने कानपुर के श्री शर्मा जो थे वे उनके प्रोजेक्ट का काम चला रहे थे। इस नाते भी आपका यह कहना है कि इस सम्बन्ध में सी. आई. ए. की वहां पर कोई एक्टीविटीज नहीं है। किस प्रकार से वे हिन्दुस्तान के अन्दर आये, हिन्दुस्तान की सरकार को यह जानकारी होते हुए भी कि वे पाकिस्तानी डेस्क से संबंधित हैं, उनको वीसा नहीं दिया गया, लेकिन उनके सहयोगी यहां के प्रोफेसरों के साथ मिलकर काम करते हैं। यह इतना गंभीर मामला है कि राजस्थान के मुख्य मंत्री जी ने स्वयं सन्दर्भ में जिक्र किया है और माननीय मंत्री जी ने उनके वक्तव्य को पढ़ा होगा। उन्होंने इस बात का जिक्र किया है और 19 तारीख का स्टेट्समैन में जो कुछ निकला है, वह मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं।

Mr. Khan said he knew there were CIA agents in the universities and political parties who visited the U. S. A. on lecture tours and accepted huge amounts for these assignments.

अभी राजस्थान के मुख्य मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया है, जिस रूप में दिया है, माननीय मंत्री महोदय ने उसकी जांच कराई होगी। एक एक देश के प्रोफेसर्स का दूसरे देश में जाना वर्जित नहीं होना चाहिये और न ही प्रजातंत्री देशों के अन्दर इस तरह की कोई बात होनी चाहिए। एक दूसरे देशों के साथ प्रोफेसरों का आदान प्रदान होता है, लेकिन जब प्रान्त का एक मुख्य मंत्री इस तरह की बात कहता है और वहां का होम डिपार्टमेंट यह बात कहता है कि वहां की युनीवर्सिटी में सी. आई. एस. की एक्टीविटीज हो रही है, तो इस दृष्टि से क्या गृह मंत्री जी ने इस सम्बन्ध में कोई जांच कराई है? उपसभापति महोदय, इस मामले की गंभीरता इस नाते से भी बढ़ जाती है कि नवम्बर में मि० ब्लू पाकिस्तान गये थे। आपने कहा कि आपको जानकारी नहीं है कि वे गंगा-नगर गए या नहीं, लेकिन कोटा वे जरूर गये

में हमारा एटोमिक इनर्जी का प्रोजेक्ट है, जो एक महत्व का प्रोजेक्ट है। वहां पर गए थे और इसके साथ ही साथ वे बीकानेर भी गये। मैं इस दृष्टि से यह कहना चाहता हूं कि हमें यह बतलाया गया कि वे इरिगेशन प्रोजेक्ट देखने गए थे। दुनिया में बहुत से बड़े प्रोजेक्ट होंगे, लेकिन लड़ाई के पहले और लड़ाई के बाद, इस बोर्डर डिस्ट्रिक्ट में बड़ी मात्रा के अन्दर पाकिस्तानी जासूस गिरफ्तार हुए थे और वे जासूस लड़ाई के दौरान जिस हालत में हमारे देश को नुकसान पहुंचा सकते हैं और विशेष तौर पर पाकिस्तानी डेस्क पर काम करने वाले लोग, अगर इस इलाके में जाते हैं तथा जिस प्रकार सेअमरीका और पाकिस्तान के संबंध है, अगर हम उनको देखें, तो यह हमारे देश के लिए बहुत ही हानिकारक चीज है। पाकिस्तान स्वय इस रूप में हिन्दुस्तान के अन्दर अपनी गतिविधियां नहीं चला सकता है, लेकिन वह अमेरिका के माध्यम से, सी. आई. ए. के एजेंटों के माध्यम से पाकिस्तान के पक्ष में जासूसी करने का काम इस समय राजस्थान के अन्दर बड़े पैमाने पर चल रहा है। माननीय गृह मंत्री जी को मालूम होगा कि 1965 की लड़ाई में बहुत बड़ी संख्या में पाकिस्तानी जासूस राजस्थान में पकड़े गये थे। वहां के मुख्य मंत्री जी ने स्वयं कहा है कि युनिवर्सिटी के अन्दर और पोलीटिकल पार्टीज के अन्दर सी. आई. ए. के एजेन्ट घुस गए हैं। मैं गृह मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि अगर राजस्थान के अन्दर किसी पोलीटिकल पार्टी के अन्दर सी. आई. ए. एजेंट घुसे हैं, तो वह आपकी पार्टी के अन्दर ही हैं। इस नाते से मैं कहना चाहता हूं कि 65 के युद्ध के समय जिनको डी. आई. आर. के अन्दर गिरफ्तार किया गया, वे कितने लोग थे ?

जिनको 65 की लड़ाई में गुप्तचरी का काम करने के लिए गिरफ्तार किया गया उनमें मंडल कांग्रेस पार्टी के सदस्य, एम. एल. ए., इस प्रकार के लोग थे जिनके लिए मिलिट्री ने कहा कि इन आदमियों ने हमको धोखा दिया, हमारी मद्रास रेजीमेंट को गुमराह किया, टीलों के अन्दर और मिलिट्री के कहने पर इनको डी. आई. आर में गिरफ्तार किया गया। वे आज कांग्रेस के एम. एल. ए. हैं, मंडल कांग्रेस के प्रधान हैं, डी. सी. सी. के मेम्बर हैं, यह सब स्वयं राजस्थान के मुख्य मंत्री ने स्वीकार किया है। तो क्या आप इसकी जानकारी करेंगे ? आज पाकिस्तान के माध्यम से वे काम न कर सकते हों लेकिन सी. आई. ए. के एजेन्टों के रूप में राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों के अन्दर घुसे हुए हैं।

श्री उपसभापति : प्रश्न पूछिए।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : प्रश्न ही है। चार लाइन का वक्तव्य देकर विषय की गम्भीरता को समाप्त किया है। आज लड़ाई के बाद भी क्या बड़े पैमाने पर इस प्रकार के लोग गिरफ्तार नहीं हुए हैं ? तो माननीय मंत्री महोदय अपनी पार्टी के अन्दर भी जांच करवाएं। केवल मुख्य मंत्री के वक्तव्य पर भी पोलिटिकल पार्टीज के अन्दर सी. आई. ए. एजेन्ट घुसे हुए हैं, उसी पर भरोसा न करें।

डा० जेड. ए. अहमद (उत्तर प्रदेश) : आप अपने यहां भी जांच करिए।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : आप अपने यहां करिए।

डा० जेड. ए. अहमद : हमारे यहां सी. आई. ए. के एजेन्ट कैसे हो सकते हैं।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : आप उनकी वकालत करने के लिए क्यों खड़े हो जाते हैं, मुझे ताज्जुब है, आप गलत बात की वकालत तो नहीं कर सकते।

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही (उत्तर प्रदेश) : श्रीमन्, माथुर साहब को ताज्जुब क्यों हो रहा

[श्री नागेश्वर प्रसाद शाही]

है। डा० जैड. ए. अहमद के वकालत करने पर उसमें फर्क ही कहां है।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : एक अमरीकन एजेन्सी कासा है, उसको खास तौर से बोर्डर डिस्ट्रिक्स के अन्दर काम दिया गया है। केवल यह मानना कि वह केवल समाज के कल्याण के लिए, गरीब लोगों के लिए, कुएं खुदवाने के लिए इस नाते से काम कर रही है, यह बिलकुल गलत बात है। केवल गरीब के दुःख से पीड़ित होकर अमरीका इतना रुपया खर्च कर रहा है, यह मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं। आज कासा एजेन्सी में राजनीतिक पार्टियों के लीडर्स को कमेटियों का मेम्बर बनाते हैं, डिस्ट्रिक्ट कमेटी में बनाते हैं, प्रान्त की कमेटी में बनाते हैं, उन लोगों को जिनको एजेंसी से रुपया मिलता है काम करने के लिए। इस बारे में मंत्री महोदय जांच करके सदन को भी बताएं और स्वयं भी अपनी जानकारी के लिए जांच करें, यह मैं निवेदन करूंगा।

श्री के. सी. पन्त : उपसभापति जी, सबसे पहले माननीय सदस्य ने कहा कि दो हिन्दुस्तान के प्रोफेसर और दो अमरीका के प्रोफेसर, वे मिल कर एक योजना में काम कर रहे थे। यह सही बात है। वे पहले करना चाहते थे, उसकी उन्होंने योजना बनाई और योजना भी सरकार को मिली। इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के रिसर्च वगैरह की योजना थी। उनमें ये दोनों अमरीकन प्रोफेसर शामिल थे, रिचर्ड न्यूटन ब्लू और डा० फोरिब और दो हिन्दुस्तानी प्रोफेसर थे डा० इकबाल नारायण और प्रोफेसर के. एन. शर्मा। इस प्रोजेक्ट को इंडियन कौंसिल आफ सोशल साइन्सेज रिसर्च ने एग्जामिन किया और उसको क्लियर नहीं किया। इसलिए वह प्रोजेक्ट ही क्लियर नहीं किया गया। जहां तक प्रोजेक्ट का सम्बन्ध है, वह क्लियर नहीं किया गया और उसमें जो प्रोफेसर न्यूटन की बात है, वह दूसरे प्रोजेक्ट के सम्बन्ध में है, यह प्रोजेक्ट तो क्लियर ही नहीं किया गया, जिसके बारे में...

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : मैंने तो यह कहा था कि वे प्रोफेसर पाकिस्तान की डेक्स पर काम करते थे, वे आए नहीं, लेकिन उनका सम्बन्ध तो परस्पर है, यह तो एस्टेब्लिश होता है।

श्री के. सी. पन्त : क्या एस्टेब्लिश होता है? आपने कहा कि इस रिसर्च प्रोजेक्ट में दो अमरीकन और दो हिन्दुस्तानी प्रोफेसर काम करते थे, लेकिन स्थिति यह है कि इण्डियन कौंसिल आफ सोशल साइन्सेज रिसर्च ने मना कर दिया और प्रोजेक्ट आगे नहीं चला, वहीं बात सत्य हो गई। (*Interruption*) जिस चीज में कुछ है नहीं, उसको बढ़ा कर कहने से फायदा नहीं। इसके जो तथ्य हैं, जहां तक मेरी जानकारी है, वे मैं आपके सामने रख रहा हूं। अब जो चीफ मिनिस्टर राजस्थान के सम्बन्ध में उन्होंने कहा कि वहां उन्होंने कुछ असेम्बली में कहा, वह अखबार की बात है, उस सदन में भी कही गई, मैं जानता नहीं कि उन्होंने क्या क्या कहा, लेकिन जो आपने मुझे बताया उससे मुझे जरूर लगता है कि वे बहुत सतर्क हैं। अगर अपनी युनिवर्सिटीज और राजनैतिक दलों के सम्बन्ध में उन्होंने यह बात कही है, तो मैं वैसे कुछ नहीं कह सकता; क्योंकि अधिकृत मेरे पास कुछ नहीं आया है, लेकिन अगर ऐसा कहा है तो वे निगरानी रख रहे हैं, सतर्क हैं और इससे आपको संतोष होना चाहिए। जो आपने कहा कि बहुत से जासूस पकड़े गए थे, यह भी निगरानी और सतर्कता का एक प्रमाण है कि बहुत से जासूस वहां पकड़े गए। अगर आप कहते कि जासूस वहां पकड़े नहीं गए तो वह लांछन होता। लेकिन जब आपने कहा कि बहुत से जासूस पकड़े गए तो यह बहुत अच्छी बात है।

डा. जेड. ए. अहमद : कुछ रह गए होंगे ।

श्री के. सी. पन्त : हां, कुछ रह सकते हैं और उनके बारे में अगर सूचना होगी तो उनके विरुद्ध कार्यवाही की जायगी । (*Interruptions*) मैं नहीं कह सकता, यह तो आपको जानकारी है, माथुर साहब ।

यह बड़ी गलत बात आपने कही कि कांग्रेस में सी. आई. ए. के एजेंट हैं । मैं इसको गैर-जिम्मेदारी की बात कहूंगा । इस तरह की गैर-जिम्मेदारी की बात किसी को नहीं कहनी चाहिए ।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : आपकी पार्टी का श्री अब्दुल हादी, एम. एल. ए., पकड़ा गया या नहीं डी. आई. आर. के अन्दर ।

(*Interruptions*)

श्री के. सी. पन्त : डा० जैड. ए. अहमद साहब ने कहा कि शायद आप की पार्टी में हों। आपने मना नहीं किया है । आपने सिर्फ यह कहा है कि ऐसी बात नहीं कहनी चाहिये । खैर, इसको जाने दीजिए । मैं समझता हूं कि पार्टियों पर इस तरह से लांछन लगाना अच्छा नहीं है ।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : मैंने यह कहा कि आपकी पार्टी के ऐसे लोग डी. आई. आर. के अन्दर पकड़े गए हैं । एक एम. एल. ए. अब्दुल हादी कर के पकड़े गये थे, यह सही है या नहीं ?

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चुंडावत (राजस्थान) : वे तीन साल पहले पकड़े गये थे और वे जन संघ ज्वाइन कर चुके है ।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : रानी जी, आप सदन में कोई एक नाम ही बता दीजिये ।

श्री के.सी. पन्त : यह जो तरीका है कि किसी एक का नाम आप कह दें और फिर यह कह कि किसी पार्टी में सी. आई. ए. के एजेंट्स भरे हुये हैं, यह बड़ा गलत तरीका है । (*Interruptions*) आपने कहा कि सी. आई. ए. के एजेंट राजस्थान कांग्रेस में हैं, यह बड़ी गलत बात आपने कही ।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : पाकिस्तान और हिन्दुस्तान की लड़ाई में अगर आपकी पार्टी के एम. ए. एल. और पी. सी. सी. के मेम्बर पकड़े जायं डी. आई. आर. के अन्दर तो इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है ।

श्री के. सी. पन्त : सी. आई. ए. के एजेंट नहीं बन जाते हैं वे इससे ।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : पाकिस्तानी एजेंट फिर वे होंगे ।

श्री के.सी. पन्त : गलत बात है (*Interruptions*) मुझे जानकारी नहीं है, इस वक्त अगर ऐसी चीज़ जाती है अखबारों में तो उससे एक गलत इम्प्रेशन बनता है । तो इस तरह की बात करना और किसी पार्टी पर इस तरह का लांछन लगाना बड़ी गैर-मुनासिब बात है ।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : मैंने कहा कि जो लोग पकड़े गये उनके लिये आप क्या कहते हैं ।

(*Interruptions*)

श्रीमती सविता बहिन (दिल्ली) : यह तो अब तक समझा जाता है और सही भी माना जाता है कि जन संघ में सी. आई. ए. के एजेंट हैं । अभी आप इस तरह की नई बात कह रहे है जो गलत बात है । इस तरह से पार्टीज़ के ऊपर लांछन लगाना सही बात नहीं है ।

उपसभापति महोदय, मैं आपके जरिये से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहती हूं कि

[श्रीमती सविता बहिन]

यह जो जानकारी लेने का तरीका है, जिससे आप का आफिस इंफार्मेशन मंगवाते हैं, वह एक ही एजेंसी या पार्टी के जरिये आती है या उसकी वैरीफिकेशन के लिये दूसरी एजेन्सी को भी भेजा जाता है।

श्री के. सी. पन्त : मैं ठीक समझा नहीं कि आप क्या जानना चाहती हैं।

श्रीमती सविता बहिन : मैं यह मालूम करना चाहती थी उपसभापति महोदय आप के जरिये माननीय मंत्री महोदय से कि जो उन का इंफार्मेशन लेने का तरीका है, अपना जो उन की पार्टी या जो आफिसेज हैं, तो वह एक ही एजेंसी से सारी इन्फार्मेशन मंगवाते हैं या उसको वेरीफाई करने के लिए किसी दूसरी पार्टी को रिचैकिंग के लिए भेजते हैं।

श्री सभापति : आप सरकार से कुछ इन्फार्मेशन चाहती हैं या उन के इन्फार्मेशन लेने के तरीके के बारे में जानना चाहती हैं ?

श्रीमती सविता बहिन : मैं सी. आई. ए. के बारे में जानना चाहती हूं। उन के बारे में सरकार का अपना जो तरीका है, उन के बारे में एक आफिस ने रिपोर्ट भेज दी उस रिपोर्ट को ही क्या सही मान लिया जाता है यह उस रिपोर्ट को रिचेक करवाने के बाद फिर सही माना जाता है ?

श्री के. सी. पन्त : अब मैं समझ गया। मसलन जिस समय विजा की बात आयी मिस्टर ब्लू की, उस की होम मिनिस्ट्री में भी जांच हुई, मिनिस्ट्री आफ एजूकेशन या इन्डियन कौंसिल आफ सोशल साइंसेज एंड रिसर्च से सलाह हुई और राजस्थान सरकार से भी सलाह हुई और जो प्रोजेक्ट आते हैं उनके संबंध में भी सलाह की जाती है, अलग-अलग मंत्रालयों से जो संबंधित हैं और जो जांच आवश्यक समझी जाती है वह सब होम मिनिस्ट्री में की जाती है। हम जो प्रोजेक्ट होते हैं उन की निगरानी भी करते हैं और देखते हैं कि वह प्रोजेक्ट किस तरह के हैं और कुछ निगरानी प्रोजेक्ट्स के संबंध में हम ने बढ़ा दी है और अध्यक्ष जी, जो जनरल सवाल है उस के उत्तर में तो चाहे सी. आई. ए. हो या दूसरे इन्टेलीजेंस आर्गेनाइजेशन हों उन पर हम निगरानी रखते हैं और जो भी राज्य के हित में कदम उठाना होता है, वह उठाते हैं। इस सारी चीज का काफी डेलीकेट क्षेत्र है जिसके बारे में इस समय बहुत सी बातें बता नहीं सकता, लेकिन मैं सदन को बताना चाहता हूं कि हम इस बारे में बहुत सतर्क हैं।

SHRl K. P. SUBRAMANIA MENON (Kerala) : I am surprised that the Minister is taking a very light view of the whole matter. There are two or three things which are significant in the whole affair. First is the date. This man, Mr. Blue, is supposed to have come to Bikaner in November 1971. And November 1971 was a significant date because on December 3 the Pakistanis had launched attack on us. Naturally, our armies and defence preparations would have been in full swing along the border districts' of Rajasthan. And there could be no doubt that that could be one of bis research problems at that time in which Mr. Blue was engaged in.

Secondly, Sir, what has an American to do with the agricultural administration in India ? I am surprised why should the Government of India give visas to any Americans to carry on research work in agricultural administration in India which is a pure and simple internal matter of the country. We should not allow anybody to do any sort of research on what sort of administration we carry on in this country, and how it is carried on etc. This is the point. It has been revealed in innumerable documents about the C.I.A. in the American press itself that the C.I.A. has been carrying on espionage activity, intelligence activity and all sorts of other activities through the agency of the co-called scholars of Universities, This has been proved that in the case of Peru, Chile and so many

other places, even in India, that they have I interfered in the internal affairs of these countries and they have instigated many anti-progressive measures. They have carried on their subversive activities through these agencies which are so-called academic pursuits.

Sir, the fourth point that has to be considered is that imperialism doss not always work through open military or economic penetration. Cultural imperialism is one of the most important aspects of subverting the national identity and national consciousness of a people. The American C.I.A. has been engaged in this work of cultural imperialism or for subverting cultural roots and ths national ideals of the people, especially poor and developing countries throughout the world. Considering all these points, is it not a fact that the Minister is taking a light view of the whole thing specially when the Chief Minister is reported to have said that there are a large number of C.I.A. agents working in the Universities in Rajasthan, taking huge sums of money from the C.I.A. or such agencies financed by the C.I.A. or which are subservient to the interest of the C.I.A.? And ths whole Government of India is taking such a light view of the whole thing. Therefore, may I know from the Government of India whether the Government of India will have a review of all the research projects now being conducted by different American universities or idividuals or academicians or whatever they are, in this country, and consider the relevance of such research projects to Indian conditions or their utility to India and stop all irrelevant and useless research activities by foreign nationals in India ? Secondly, I would like to know whether the Government of India will review all the grants and other props given to Indian scholars to go abroad on research followships from American universities or American agencies, so as to prevent the corruption and subversion of their Ijyalty to this oj.itry. TntrJIy, I woald like to know whether ths Government will consider thit in future, all ths research projects wnich are to be financed from abroad, should be routed through one of ths agencies of the Government of India like, say, the Indian Council of Social Sciences Research vetted by it as to their probablfc utilisation by foreign agencies against this country or its interests.

SHRI K, C. PANf : Sir, I have already indicated that a careful scrutiny is being made of the various research projects and exchange programmes. In fact, I have indicated that it is as a result of this scrutiny that the other project, which involved two Indian and two American Professors, was not acce ted on the advice of the Indian Council of Social Sciencers Research. Therefore, screening is being dons and that is what I have indicated earlier.

Now, about the visit of Prof. Blue to Bifcaner in 197:, my information is that he went there on the II th and 12th of Nsvem-ber, 1971. The State Government have no information about the indulgence of Mr. Blue in CIA activities. . .

SHRI K. P. SUBRAMANIA MENON: Obviously he will not inform the State Government of what he is doing.

SHRI K. C. PANT: Obviously the State Government have their own ways of finding out. And my information also is...

SHRI BHUPESH GUPTA : If the way is obvious, then it is hardly the way to find out.

SHRI K. C. PANT : It is obvious perhaps to you but not to the person cancerned. You are supposed to be in the know of many things which they do not know.

As I said, screening is already being done.

SHRI K. P. SUBRAMANIA MENON : It is not effective.

SHRI K. C. PANT : It is no use interrupting me. I have said that screening is done. The Education Ministry is there. The Indian Council of Social Sciences re Reseasah is there. These are the people who go into these matters. There are experts and itis for them to go into this.

So far as ths revelations in the American press regarding the CJA activities go, I can assure my hon. friend that we are fully alive to these revelations. In 1966 wh»n these things came out tn the *New York*

[Shri K. C. Pant] *Times*, we took nole of all those things. We took note of them and of the conduit agencies. We are certainly particularly watchful about all these revelations and the implications of these revelations. That I can assure him. Then, as far the subverting of the national identity and the cultural roots of this country, I do not think that these are matters which can be subverted by a few CIA agents. I do not share my hon. friend's apprehension in this regard;

डा० जैड० ए० अहमद: मैं मंत्री महोदय से बहुत संजीदगी के साथ अर्ज़ करूंगा और उनसे कुछ जवाब की दर्ख्वास्त करूंगा । चूंकि यह मसला घड़ी-घड़ी यहां उठता है इसलिए इसके साथ एक दफा निपट लिया जाए—मतलब यह है कि खास ध्यान देकर इस पर जांच करवा ली जाए । अभी तक हम उठाते थे, अब जन संघ ने भी उठाना शुरू कर दिया । मुझे यह बात समझ में नहीं आई कि आज जन संघ ने यह सवाल उठाया...

श्री नवल किशोर (उत्तर प्रदेश): वे आपके नज़दीक आ रहे हैं ।

डा. जैड. ए. अहमद:...क्यों और कैसे ? मैं नहीं जानता । मगर, बहरहाल, उन्होंने भी इस सवाल को उठा दिया ।

अब हक़ीक़त यह है कि ये इधर-उधर घुसते हैं—अग्रिकलचर युनिवर्सिटी में, दूसरी युनिवर्सिटी में । तो इनकी बाकायदा स्पेशल ड्राइव की तौर पर स्क्रीनिंग कर दी जाए । नम्बर 2, उनके इर्दगिर्द जो हिन्दुस्तानी हैं, क्योंकि खाली अमरीकन का सवाल नहीं है, ये अपने पैसे अपने इर्दगिर्द हिन्दुस्तानियों का सर्किल बना लेते हैं, चाहे कांशस एजेन्ट हों चाहे अनकांशस एजेन्ट हों, लेकिन उनका काम करने का जो सर्किल बनता है उसकी भी जांच होनी चाहिए । और मैं खास तौर से कहना चाहता हूं, उनका सम्पर्क बड़े बड़े सरकारी अफसरों से भी काफी होता है । उसकी भी मैं समझता हूं जांच करवानी चाहिए कि बड़े बड़े अफसरों के ज़रिए कितना काम निकाल लेते हैं, कितनी इन्फार्मेशन निकाल लेते हैं । इसकी जांच होनी चाहिए । ये सब जांच हो जाए, इसके साथ साथ मेरी खास दर्ख्वास्त यह है कि गवर्मेन्ट इस मसले पर ध्यान दे और सोचे कि पी. एल. 480 फन्ड्स को फ्रीज किया जाए क्योंकि वह एक सोर्स है जिसके ज़रिए काम काफी निकलता है—सी. आई. ए. एजेन्टेस से । मंत्री महोदय कहते हैं हम विजिलेन्ट है उनके बारे में और दूसरों के बारे में । लेकिन दूसरों का और उनका मुकाबला नहीं किया जा सकता । एक विश्वव्यापी आर्गेनाइजेशन है, उसके बारे में सब जानते है क्या कर रहे है एशिया में, साऊथ अमरीका में और दूसरे मुलकों में । तो इसकी तरफ खास ध्यान देना चाहिए । और आप यह कहें कि हमने फलां एजुकेशन डिपार्टमेन्ट के फलां सेक्शन को बताया इस प्रोजेक्ट को देखने के लिए—वह काफी नहीं है, क्योंकि सवाल पोलिटिकल भी होते हैं, सिर्फ टेकनिकल मामला नहीं है कि प्रोजेक्ट रिसर्च के वास्ते उनको इजाज़त दी जाए या न दी जाए । यह सियासी मामला है । तो सियासी दृष्टि से इन प्रोजेक्ट्स की स्क्रनीग के लिए कोई आर्गेनाइजेशन या सेल आपकी तरफ से बनना चाहिए ताकि ठीक तौर से इस मसले को संभाला जा सके और हाऊस को संतुष्ट किया जा सके जितनी बात आप कहें उससे ।

श्री नवल किशोर: आपने बहुत संजीदगी से बात कही है ।

श्री के. सी. पन्त : उपसभापति जी, अब मैं यह नहीं कह सकता, अधिकृत रूप से, कि क्यों जन संघ ने उठाया । तो अगर आप इजाज़त दें, तो उस सदन में एक बात उठी थी कि डा० इक़बाल नारायण शायद मुसलमान हैं...

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : हमने कहां कहा है ?

श्री के. सी. पन्त : आपने नहीं कहा आपके साथी जोशी जी ने कहा इससे इसकी जड़ निकलती है। (*Interruption*) मैं एक बात बता दूं...

डा. जैड. ए. अहमद: क्या नारायण इकबाल हैं ?

SHRI N. G. GORAY (Maharashtra) That is reported also in the press.

श्री के. सी. पन्त : डा. इकबाल नारायण है। इसलिए उन्होंने कहा, शायद मुसलमान हैं । तो यह सवाल की जड़ हो गई...

श्री जगदीश प्रसाद माथुर: आपके दिमाग में ही एक बात जड़ कर गई । हमारे पास इलाज नहीं है ।

श्री के. सी. पन्त जोशी जी सतर्क नहीं रहे । उनसे बात निकल गई इकबाल नारायण हम समझते थे कि हिन्दू हैं...

श्री मान सिंह वर्मा (उत्तर प्रदेश) : मंत्री जी अपनी बात कहें, दूसरों के ऊपर डालने का प्रयत्न क्यों करते हैं ।

श्री के. सी. पन्त: हम क्या करें । आपको बुरा लग गया । (*Interruption*) अब जो आपने यह कहा कि निगरानी रखनी चाहिए । तो इसकी डिटेल्स तो मैं ज़ाहिर है, नहीं दे सकता लेकिन निगरानी रखी जाती है जहां आवश्यक होता है जहां जरूरी समझा जाता है । पी. एल. 480 फंड के सबंध में अपने कहा तो मैंने अभी अपने फाइनेन्स मिनिस्ट्री के साथी से पूछा । उन्होंने कहा पी. एल. 480 के फुल फैक्ट्स फाइनेन्स मिनिस्ट्री के पास हैं...

SHRI BHUPESH GUPTA (West Bengal): Rupees 249 crores are now earmarked for the expenditure of American missions in this country, according to the latest figure given to us.

SHRI K. C. PANT : He has answered a question recently on the subject in which he has given the information with him. He said just now, only recently he has given the full facts to the House.

आखिर में आपने कहा कि पोलिटिकल नज़रिए से इसकी स्क्रीनिंग होनी चाहिए । यह बात सही है कि इसमें एक सियासी नज़रिया होना चाहिए और होम मिनिस्ट्री में सियासी नज़रिए से भी इसको देखा जाता है ।

श्री नवल किशोर: श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि जैसा कि राजस्थान के चीफ मिनिस्टर ने कहा कि सी. आई. ए. के एजेन्ट्स युनिवर्सिटीयों में काम करते हैं । उन्होंने इसकी मिसाल यह दी कि बहुत से प्रोफेसर्स युनिवर्सिटियों से यू. एस. ए. जाते हैं और वहां पर लेक्चर टुअर के नाम पर जाते हैं और काफी पैसा वहां से उनको मिलता है । तो क्या मंत्री जी यह बता सकेंगे कि जो इस तरह के प्रोफेसर जाते हैं अमरीका को क्या उनको डाइरेक्ट इन्विटेशन वहां की युनिवर्सिटी से मिलता है या किसी तरह से उनकी कोई छान-बीन होती कि उनको किस प्रोजेक्ट के किए इन्विटेशन मिला है और वह कैसे मिला है और और कहां से मिला है ।

दूसरी बात यह है कि जो प्रोजेक्ट आप देते हैं, रिसर्च प्रोजेक्ट देते हैं, चाहे वे एक्सचेन्ज के अखार पर ही क्यों न हों, जब उनको किसी स्टेट में चलाया जाता है तब क्या इस बारे में स्टेट गवर्नमेंट्स से कंसल्ट किया जाता है कि इन प्रोजेक्टों को दिया जाय या नहीं ? क्योंकि अखबार में पढ़ने मालूम होता है कि चीफ मिनिस्टर ने यह शिकायत की है, उनका कहना यह है कि कोई भी इस तरह का प्रोजेक्ट स्टेट को न दिया जाय जबतक स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से क्लियरेंस न हो जाय । मैं यह जानना

[श्री नवल किशोर]

चाहता हूं कि इस बारे में गवर्नमेंट आफ इंडिया की पालिसी क्या है ? क्या वह आयन्दा इस तरह के प्रोजेक्टों के बारे में स्टेट गवर्नमेंट्स से पहले कन्सल्ट कर लेगी और जब स्टेट गवर्नमेंटस इस बारे में ग्रीन सिगनल दे दे, तभी वह इस तरह के प्रोजेक्टों के सम्बन्ध में मंजूरी देगी मैं यह बात जनना चाहता हूं ।

श्री के. सी. पन्त : उपसभापति जी, जो हिन्दुस्तान के प्रोफेसर जाते है उनके सम्बन्ध में क्या इस वक्त नियम है, यह मैं नहीं कह सकता हूं । मैंने तो इस के बारे में जानकारी प्राप्त की थी जो वहां से आते हैं । जहां तक स्टेट गवर्नमेंट से कंसल्ट करने की बात हैं, स्टेट गवर्नमेंट से इस मामले में कंसल्ट किया गया और यह डिपार्टमेंट आफ पोलिटिकल साइन्स, युनीवर्सिटी आफ राजस्थान, जयपुर ने, उनको एक एफिलियेट बनाया 1971-72 के लिए और इसके अलावा गवर्नमेंट से भी पूछा गया ।

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : पी. एल. ए. 480 फंड से हिन्दुस्तान की बहुत सी संस्थाओ को सहायता दी जाती है और विशेष तौर पर देश के कृषि विश्वविद्यालयों को इस फंड से काफी सहायता मिलयो है । मुझे ज्ञात है कि ऐसे कुछ विश्वविद्यालयों को जिन्हें 480 फंड के मातहत सहायता मिलती है, उनमें से प्राध्यापकों का चयन जो कमेटी करती है उसमें अमरिकन एक्सपर्ट बैठते हैं । यह भी ज्ञात हुआ है कि इन चयन कमेटियों का निर्णय अमेरिकन एक्सपर्ट की राय पर ही होता है और ब्रौडली वे ही इस तरह का निर्णय करते हैं । जो हिन्दुस्तानी इन कमेटियों में बैठते हैं उनकी हेम्मत भी नहीं होती कि वे अमेरिकन एक्सर्टस की राय की मुखालिफत करें क्योंकि उन्हें यह शंका बनी रहती है कि अगर हम एक्सपर्टस की राय को मानकर नहीं चलेंगे, उनकी राय से उनका चयन होने देंगे, तो वे प्रोफेसरों को आर्थिक सहायता बन्द कर देंगे । इस तौर पर इन संस्थाओं में जो प्राध्यापक नियुक्त होते हैं वे वही लोग होते हैं जिनका चयन अमेरिकन एक्सपर्ट करते है और उनके माध्यम से सी. आई. ए. वालों को एक मौका मिल जाता है कि अपना सम्पर्क इन लोगों से कायम करे तथा अपने एजेन्टों को देश के विश्वविद्यालयों में घुसा दें । क्या सरकार तरह की कोई व्यवस्था बनाने की बात सोचेगी आर्थिक सहायता देने के बावजूद भी, इन संस्-थाओं और विश्व-विद्य लयों कि प्राध्यापकों के चयन तथा नियुक्ति में अमेरिकन एक्सपर्ट का हाथ नहीं होगा ?

श्री के. सी. पन्त : उपसभापति जी, जैसे मैंने पहले कहा कि इसका कोई आधार नहीं है कि केबल अमेरिकनों के कहने पर या किसी कमेटी के कहने पर यह हो जाता है कि किस प्रोजेक्ट को कितना पैसा दिया जाय और कहां दिया जाय ।

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : मेरा प्रश्न यह नहीं है ।

श्री के. सी. पन्त : आपने अभी कहा कि एक कमेटी है जो चयन करती है कि किस योजना के लिए कितना पैसा दिया जाय । इस कमेटी में अमेरिकन एक्सपर्ट बैठते है और उनकी ही बात वहां पर चलती है तथा वे अपनी बात वहां पर मनवा लेते हैं ।

श्री नागेश्वर प्रशाद शाही : मेरा प्रश्न दूसरा है । इन विश्व-विद्यालयों में जिनको इस फंड से रुपया मिलता है, उनमें प्रोफेसरों का जो सलेक-शन होता है, उन सलेक्शन कमेटियों मे अमेरिकन एक्सपर्ट बैठते हैं, अमेरिकन युनीवर्सिटीज के डीन्स बैठते हैं । मैं दो, तीन युनीवर्सिटिज के नाम जानता हूं. आपकी पन्त नगर युनीवर्सिटी उनमें से एक है । इस तरह से उनके माध्यम से सी.

आई. ए. वालों को सम्पर्क करने का मौका मिल जाता है और इस तरह से वह लोग अपने एजेन्ट प्रोफेसरों को एपाइन्ट कर लेते हैं। क्या आप इस बारे में कोई व्यवस्था करेंगे, जिससे इन सलेक्शन कमेटियों में अमेरिकन एक्सपर्ट न बैठे ?

श्री के. सी. पन्त . यह तो आपने मेरा काम बड़ा हल्का कर दिया क्योंकि पन्त नगर यूनीवर्सिटी की गवर्निंग बोडी में मैं भी हूं और वहां का क्या प्रोसीजर है वह मैं बता सकता हूं।

डा. जैड. ए. अहमद : बता दीजिए, हम भी जानना चाहते हैं।

श्री के. सी. पन्त: जो भी सेलेक्शन कमेटी होती है उसकी सिफारिशें गवर्निंग बोडी के सामने आती है और गवर्निंग बोडी फैसला करती है कि किसको लिया जाय, किसको न लिया जाय। बाहर से किसी आदमी को लेने का प्रश्न नहीं उठता अगर हिन्दुस्तान में कोई आदमी ऐसा मिल जाय जो उस काम को कर सकता हो। इसलिए वह तो ऐसा प्रोसीजर है जिसमें किसी अमरीकन की बात चलने का सवाल नहीं है। अगर कोई अमरीकन अच्छी सलाह दे तो उसे मान लेना चाहिए, लेकिन गवर्निंग बोडी के सामने सारी चीज आती है, गवर्निंग बोडी में जिम्मेदार लोग बैठते हैं राज्य सरकार के और केन्द्रीय सरकार के एम. एल. ए. और शायद एम. पी. भी और हर बात को ठोक-पीट कर देखते हैं।

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : पन्त जी उस कमेटी में होंगे, लेकिन आज से 5-6 साल पहले मैं उस कमेटी में था। मैं जानता हूं कि एक नहीं, तीन-तीन अमरिकन एक्सपर्ट सेलेक्ट कमेटी में बैठते हैं, नाम भी याद है और सेलेक्ट कमेटी ने 12 आदमी सेलेक्ट किए थे उनमें अमरीकन एक्सपर्ट ने अपने सारे लोगों को लिया था।

श्री के. सी पन्त : मैंने स्पष्ट किया कि मैं सेलेक्शन कमेटी में नहीं हूं, गवर्निंग बोडी में हूं।

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : गवर्निंग बोडी में भी उन्हीं लोगों की चलती हैं।

श्री के. सी. पन्त : यह बात सही नहीं है।

श्रीमती सीता देवी (पंजाब) : माननीय मंत्री जी ने बड़े विस्तार से इस बात को बताया है कि गवर्नमेंट बहुत सतर्क रहती है। कुछ हद तक रहती भी है, पर मैं यह कहना चाहता हूं कि सतर्क रहते हुए भी जिस तरह से सतर्क रहना चाहिए उस तरह से सतर्क नहीं रहती। अगर उस तरह से सतर्क होती तो आए दिन कोई न कोई घटना हमारे सामने आती है और जिसको फ्लोर आफ हाउस पर, राज्य सभा में और लोक सभा में मिनिस्टर साहब खुद भी स्वीकार कर चुके हैं वह न होती अभी दो साल पहले राज्य सभा में एक प्रश्न के उत्तर में उस वक्त हमारे गृह मंत्री माननीय चव्हाण जी थे उन्होंने स्वीकार किया था कि एशिया फाउन्डेशन को अमरीका के गुप्त विभाग से पैसा मिलता है और अभी 13 अप्रैल को श्री सुरेन्द्र पाल सिंह जी ने भी एक प्रश्न के उत्तर में ऐसा स्वीकार किया। तो मैं यह कहना चाहती हूं कि आपकी नौलेज में यह होना चाहिए था कि डा. बलू और डा. प्रोरिब का उनकी शिक्षा की दृष्टि से एग्रीकल्चर और सिंचाई से कोई सम्बन्ध ही नहीं है। कम से कम सरकार को इस बात को देखने की कोशिश करनी चाहिए कि उन्होंने गंगा नगर और बीकानेर की सिंचाई व्यवस्था, केनाल की और बड़े-बड़े रेत के टीलों की विस्तृत जानकारी और नक्शे बना कर दूसरे देशों को दिए। यह कोई नई चीज नहीं है। दुनिया भर के देशों में सी आई ए छद्म रूप से काम करती है। जब खुश्चेव और बुल्गानिन इंगलैंड में थे,

[श्रीमती सीता देवी]

उनका जहाज बन्दरगाह में खड़ा था, बाद में पता लगा कि इंगलैंड का एक फ्रागमेन मिसिंग है। उस समय सब चुप रहे, फिर 3 साल के बाद पता लगा कि वह फ्रागमेन रूसियों के पास था। ये इंस्टेंसेज मैं इसलिए दे रही हूं क्योंकि सी. आई. ए. अभी बड़े जोरों से काम कर रही है। ढाका के पतन के बाद में भी आपने अखबारों में पढ़ा होगा—मुझे जाने का अवसर नहीं मिला—कि वहां पर लोग प्रशिक्षण दे रहे हैं। तो ऐसी घटना जो अभी सामने आई है बोर्डर स्टेट की, यह हमारे पंजाब में भी और स्टेटों में भी हो रहा है और मेरा ख्याल है कि हमसे मिनिस्टर साहब को ज्यादा नालेज है कि ये लोग शिक्षण संस्थाओं में, कालेजों में, अखबारों के अन्दर और अखबार वालों के द्वारा भी अपना काम करते हैं। इस लिए मैं तो केवल यही कहना चाहती हूं जैसा कि उनको नालेज में होगा, कि काशी विश्वविद्यालय में सी. आई. ए. के दो प्रोजेक्ट चल रहे हैं। वाइस चांसलर को पता नहीं था, नई कौंसिल जो बनी उसने एक्शन लिया। मैं यह बताना चाहती हूं कि ये लोग किस तरह से हर एक संस्था के अन्दर, कालेज के अन्दर, स्कूलों में, संस्थाओं में किसी न किसी रूप में घुसकर अपना काम करते हैं। तो हमारी सरकार को और भी सतर्क रहने की जरूरत है। खास तौर इस युद्ध में पाकिस्तान और अमरीका का जो हमारे साथ व्यवहार रहा उसे देखते हुए हमें बहुत ज्यादा एलर्ट होने की जरूरत है ताकि भविष्य में इस किस्म की गड़बड़ न हो सके।

श्री के. सी. पन्त : उपसभापति जी, जो माननीय सदस्य ने कहा कि आये दिन ऐसी घटनाएं घटती हैं, ऐसी बात तो कोई है नहीं और इसमें भी जो मैंने आपको तथ्य दिये उसके आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि यह कोई ऐसी घटना है जिसके बारे में कोई चिन्ता हो। आपने कहा कि इस योजना को क्यों स्वीकार किया। मैंने बतलाया कि विशेषज्ञों ने इसको स्वीकार किया। मैं विशेषज्ञ नहीं हूं और मैं नहीं बतला सकता कि स्वीकार कैसे किया, कैसे नहीं किया, लेकिन जिनकी जिम्मेदारी है उन्होंने इसको स्वीकार किया। और आप ने कहा कि गंगानगर में उन्होंने नहरों ने नक्शे बनाये, तो मैंने अपने वक्तव्य में बतलाया कि गंगानगर वह गये नहीं, मेरे पास इस की कोई सूचना नहीं है। वह बीकानेर एक दो दिन के लिए गए थे और वहां के लिए कोई सूचना नहीं है राजस्थान सरकार के पास से या हमारे पास कोई सूचना ऐसी नहीं है कि उन्होंने वहां नहरों के कोई नक्शे बनाये या कोई ऐसा काम किया जो आपत्तिजनक हो। तो मैं यह पहले भी बता चुका था अपने वक्तव्य में ही। काशी विश्वविद्यालय में अब कोई सी. आई. ए. का प्रोजेक्ट कोई प्रोजेक्ट हो यह बड़ी अनहोनी सी बात लगती है। अगर मालूम होता तो हम कभी ऐसे प्रोजेक्ट को नहीं होने देते। यह बात या तो आपने गलतफहमी से कही, या आप कोई दूसरी बात कहना चाहती हों और उसके बजाए ऐसा कह गईं, तो यह हो ही नहीं सकता कि जानबूझ कर कोई ऐसा प्रोजेक्ट हम वहां चला देते। जो सतर्कता की बात आपने कही, उसके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं कि हमें सतर्क रहना चाहिए और हम सतर्क है।

श्रीमती सीता देवी : मैं क्लियरली दो प्वाइन्ट जानना चाहती हूं। मिनिस्टर साहब ने यह कहा कि वह बीकानेर गये ही नहीं, मैंने अखबारों में पढ़ा था कि···

श्री उपसभापति : गंगानगर के लिए उन्होंने कहा था।

श्रीमती सीता देवी : मैंने एक रेफरेंस में पढ़ा था कि वहां के मुख्य मंत्री ने एक प्रश्न के उत्तर में यह कहा था कि वह वैसे नहीं गये, साइट सीइंग के लिए गए और साइट सीइंग के बहाने बहुत सी जगहों पर जाया जा सकता है।

(*Interruption*)

PAPERS LAID ON THE TABLE

REPORT (1970-71) ON THE ACTIVITIES OF THE RUBBER BOARD, KOTTAYAM AND RELATED PAPERS

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOREIGN TRADE (SHRI A. G. GEGRGE) : Sir, I beg to lay on the Table a copy of the Report on the activities of the Rubber Board, Kottayam, for the year 1970-71, together with a statement (in English and Hindi) giving reasons for not laying simultaneously the Hindi version of the Report. [Placed in Library. See No. LT—3023/72].

I. ANNUAL REPORT AND ACCOUNTS(1970-71) OF THE MADRAS FERTILISERS LIMITED AND RELATED PAPERS

H. ANNUAL REPORT AND ACCOUNTS (1970-71)OF THE PYRITES PHOSPHATES AND CHEMICALSLIMITED AND RELATED PAPERS

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT (SHRI DALBIR SINGH) : Sir, I beg to lay on the Table a copy (in English and Hindi) each of the following papers, under sub-section (1) of section 619A of the Companies Act, 1956 :—

I. (i) Fifth Annual Report and Accounts of the Madras Fertilizers Limited, for the year 1970-71, together with the Auditor's Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.

(ii) Review by Government on the working of the Company. [Placed in Library. See No. LT—3083/72 for (i) and (ii)].

II. (i) Eleventh Annual Report and Accounts of the Pyrites, Phosphates and Chemicals Limited, for the year 1970-71, together with the Auditors' Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India ihereon.

(ii) Review of Government on the working of the Company. [Plactd in Library. See No. LT—3057/72 for (i) and (ii)]

THE KEROSENK (F[XATION OF CEILING PRICES) THIRD AMENDMENT ORDER, 1972.

SHRl DALBIR SlNGH : Sir, I also beg to lay on the Table a copy (in English and Hindi) of the Ministry of Petroleum Chemicals Notification G. S. R. No. 276 (E), dated the 8th May, 1972, publishing the Kerosene (Fixation of Ceiling Prices) Third Amendment Order, 1972, under sub-section (6) of section 3 of the Essential Commonities Act, 19i5. [Placed in Library. *See* No. LT—2082/72].

PRESENTATION OF PETITION BY THE EMPLOYEES OF THE CATERER RUNNING THE CANTEEN ATTACHED TO THE CENTRAL GOVERNMENT HOSTEL, NIZAM PALACE, CALCUITA RE. THEIR SERVICE CONDITION

SHRI SASANKASEKHAR SANYAL (West Bengal) : Sir, I beg to present a petition signed by twelve employees of the Caterer who is running the canteen attached to the Central Government Hoslel, Nizam Palace, Calcutta, regarding their service ondition.

LEAVE OF ABSENCE TO SHRl SITARAM JAIPURIA

MR. DEPUTY CHAIRMAN : I have tc inform Members that the following letter dated the 15th May, 197k., has been received from Shri Sitaram Jaipuria :

"I am leaving for foreign countries on the 18th of May, and wi)l not therefore be able to attend the rest of the current session. Leave of absence may therefore kindly be granted to me."

Is it the pleasure of the House that permission be granted to Shri Sitaram Jaipuria for remaining absent for the rest of the meetings of the House during the current session ?

(No. hon. Member dissented.)

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Permission to remain absent is granted.